क्या इरादे, क्या सबूत

सिर्फ लूट, सिर्फ झूठ

कांग्रेस सरकार ने किया 15 सालों में दिल्ली को बर्बाद !

भाजपा आएगी,
दिल्ली मुस्करायेगी

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश

अर्थव्यवस्था

- वृद्धि दर–दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले पांच वर्षों से दिल्ली सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मामले में दूसरे स्थान पर रही है, लेकिन तथ्य कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं: वित्त वर्ष 2005–06 में दिल्ली 18वें, वित्त वर्ष 2006–7 में 9वें, वित्त वर्ष 2007–08 में 9वें, वित्त वर्ष 2008–09 में 12वें, वित्त वर्ष 2009–10 में 17वें, वित्त वर्ष 2010–11 में 18वें और वित्त वर्ष 2011–12 में 15वें स्थान पर रही।

- अपने नियंत्रण वाले तुलनात्मक क्षेत्रों वाली सरकारों के बीच, दिल्ली इन वर्षों के दौरान लगातार निचले पायदान पर रही है। चण्डीगढ़, गोवा, सिक्किम और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहों में इस अवधि के दौरान बेहतर वृद्धि दर दर्ज की गई है। वृद्धि के आंकड़ों में, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की तुलना में, दिल्ली का स्थान काफी नीचे रहा है।

- जीडीपी के संदर्भ में दिल्ली में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर की स्थिति भी अच्छी नहीं रही है। जीडीपी के संदर्भ में वित्त वर्ष 2004–05 की तुलना में वित्त वर्ष 2005–06 में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर के मामले में दिल्ली का स्थान 11वां रहा, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से भी कम था। वित्त वर्ष 2005–6 की तुलना में वित्त वर्ष 2006–07 में दिल्ली का स्थान देश में 17वां था, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम था। वित्त वर्ष 2006–07 की तुलना में वित्त वर्ष 2007–08 में दिल्ली का स्थान 14वां था, वह एक बार फिर से राश्ट्रीय औसत से काफी पीछे थी। वित्त वर्ष 2007–08 की तुलना में वित्त वर्ष 2008–09 में दिल्ली 13वें स्थान पर थी और यह राष्ट्रीय वृद्धि दर से मामूली ऊपर था। वित्त वर्ष 2008–09 की तुलना में वित्त वर्ष 2009–10 में दिल्ली का स्थान 10वां था और राष्ट्रीय वृद्धि दर से ज्यादा था, वित्त वर्ष 2009–10 की तुलना में वित्त वर्ष 2010–11 में दिल्ली 9वें स्थान पर थी। इन आंकड़ों में महाराष्ट्र जैसे राज्यों को शामिल नहीं किया गया है और दिल्ली की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से करीब 2 प्रतिशत नीचे रही है। ऐसे में कोई सरकार भला कैसे अच्छी अर्थव्यवस्था का दावा कर सकती है, जबकि उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर इतना खराब रहा हो?

- खरीदने की क्षमता की समतुल्यता के मामले में दिल्ली का जीडीपी मुंबई से पीछे है। मुंबई का वैश्विक दर्जा 29वां, और दिल्ली का 37वां है, जबकि मुंबई की अपनी सरकार भी नहीं है।

सम्पादक मंडल

श्री जगदीश मुखी, विधायक
श्री साहिब सिंह चौहान, विधायक
श्री कुलवंत राणा, विधायक
श्री जय भगवान अग्रवाल, विधायक
श्री रविन्द्र बंसल, विधायक
श्री हरीश खुराना

बेरोजगारी

- दिल्ली सरकार का दावा है कि वह दिल्ली में बेरोजगारों की संख्या में कमी लाई है, लेकिन इन 15 वर्षों में वह सिर्फ अपने आंकड़ों में ही बेरोजगारी के आंकड़ों में महज 2 लाख की कमी कर सकी है और उसने रोजगार में फेरीवालों, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शाचालकों आदि को शामिल किया है।

- सरकार ने जानबूझकर यह तथ्य छुपाया है कि 15 वर्ष पहले से, जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, तब से बेरोजगारी की दर में दरअसल वृद्धि हुई है। वित्त वर्श 1999–2000 में बेरोजगारी की दर 3.6 प्रतिशत थी जबकि अब 4.0 प्रतिशत है। इस प्रकार दिल्ली में बेरोजगारी काफी बढ़ी है।

- पिछले 10 वर्षों के दौरान दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 11242 लोगों को नौकरी प्रदान की गई। इस अवधि के दौरान इन रोजगार कार्यालयों में 1016328 बेरोजगारों ने पंजीकरण करवाया।

- दिल्ली सरकार में पिछले 10 वर्षों के दौरान 91585 पद रिक्त थे। इनमें से 62020 पद अब तक रिक्त हैं।

वित्तीय अनुशासन

- कांग्रेस सरकार का कहना है कि उसने दिल्ली के वित्तीय अनुशासन में सुधार किया है।

- वास्तविकता यह है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने दिल्ली सरकार के दावे की हवा निकाल दी है।

- सीएजी के अनुसार, दिल्ली सरकार के खराब नियोजन और अपर्याप्त कर उगाही की वजह से 2700 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई है।

- छूट के अनियमित दावों और दिल्ली सरकार की कर उगाही प्रणाली की अन्य खामियों के कारण 404 करोड़ रुपये ब्याज सहित 2310 करोड़ रुपये कर का कम भुगतान हुआ।

स्वास्थ्य

आरटीआई आवेदन के माध्यम से मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (डीएसएचएम) के तहत आवंटित 31,069.13 रुपयों में से वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान महज 28.9 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया।

निम्नलिखित आंकड़े दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होने के कांग्रेस के दावों की पोल खोल देते हैं, क्योंकि इनमें दर्शाया गया है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित धन को खर्च ही नहीं कर सकी।

गतिविधि	स्वीकृत बजट	प्रतिशत
मातृ स्वास्थ्य	23.14 करोड़ रुपये	10.3 प्रतिशत
बाल स्वास्थ्य	4.25 करोड़ रुपये	5.75 प्रतिशत
परिवार नियोजन	4.39 करोड़ रुपये	24.7 प्रतिशत
नव–निर्माण / मरम्मत	45.92 करोड़ रुपये	3.24 प्रतिशत
मोबाइल मेडिकल यूनिट	46.45 करोड़ रुपये	0.0 प्रतिशत

कांग्रेस सरकार दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में बिस्तरों और चिकित्सकों की उपलब्धता की दर बहुत निराशाजनक है। दिल्ली में प्रति एक हजार व्यक्तियों पर महज 2.5 बिस्तर हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार, प्रति एक हजार व्यक्तियों पर 5 बिस्तर होने चाहिये।

दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत महज 3578 बीपीएल परिवारों को शामिल किया गया है। इस पर महज 4.39 लाख रुपये खर्च किये गए हैं।

दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, वास्तविकता यह है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता निशानजनक रूप से कम है। यहां प्रति 10,000 व्यक्तियों पर 2 से भी कम क्लीनिक्स हैं।

दूसरी ओर, सीएजी ने साल दर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट्स में विविध स्वास्थ्य संकेतकों पर सरकार की आलोचना की है।

वर्ष 2013 की सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंसों का या तो दुरुपयोग किया गया जाता है या फिर उनका इस्तेमाल ही नहीं होता, और तो और उनमें बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है।

सीएजी के अनुसार, भयावह स्थिति यह है कि इन एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन सिलेंडरों, सक्शन पम्पस, स्टेथोस्कोप्स और फर्स्ट एड बॉक्सिज जैसी बुनियादी जीवन रक्षक प्रणालियों का भी अभाव हैं।

ऑडिटर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शहर के कई अस्पतालों में बहुत सी आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली के तकरीबन सभी सरकार अस्पतालों में शुद्ध, स्वच्छ पेय जल की सुविधा का अभाव है।

वर्ष 1997 और 2008 के बीच आवंटित 60–700 के बीच की क्षमता वाले 10 अस्पतालों की जमीन पर अब तक निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हुआ है।

एक चौंका देने वाली कमी के रूप में यह पाया गया कि 5 अस्पतालों में ब्लड बैंक्स् नहीं हैं, जबकि जीटीबी अस्पताल के ब्लड बैंक के लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया गया है।

दिल्ली सरकार ने 2900 बिस्तरों की क्षमता वालें 12 नए अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो सका।

द्वारका में (750 बिस्तर), विकासपुरी में (200 बिस्तर), मादीपुर में (200 बिस्तर), ज्वालापुरी में (200 बिस्तर), अम्बेडकर नगर में (200 बिस्तर) के अस्पतालों के निर्माण में पहले ही काफी देरी हो चुकी है।

मार्च 2013 में 11 सरकारी अस्पतालों को अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं मिला था।

दिल्ली को हर साल डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से जूझना पड़ता है, इसके बावजूद नेशनल वेक्टर–बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम (एनवीबीडीसीपी) के कार्यान्वयन पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया, जबकि इसके लिए करीब 6.2 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे।

सरकार ने मातृ स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से बनाये गये प्रमुख कार्यक्रमों पर बहुत कम (राशि का 10.03 प्रतिशत) खर्च किया। इनमें जननी सुरक्षा योजना और बाल स्वास्थ्य (राशि का 5.75 प्रतिशत) शामिल है।

शिशु मृत्यु-दर

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के दिल्ली सरकार के दावों के बावजूद, एक आरटीआई आवेदन से पता चला है कि पिछले 5 वर्शों में शहर के अस्पतालों में 50,000 शिशुओं की मृत्यु हुई।

इसका आशय यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में हर साल औसतन 10,000 शिशुओं की मृत्यु होती है।

प्रति 1000 बच्चों के जन्म पर 28 मौतों की शिशु मृत्यु दर की वजह से दिल्ली सरकार के लिए वर्ष 2015 तक 10 के लक्ष्य को प्राप्त करना दुर्गम है। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा करती है।

अस्पताल में ईडब्ल्यूएस

कांग्रेस सरकार का दावा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों (ईडब्ल्यूएस) का निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जाता है।

हकीकत कुछ और है। और तो और सरकार के अपने रिकॉर्ड के अनुसार यह स्पष्ट है कि चिन्हित किये गए 43 निजी अस्पतालों में से कम से कम 34 ईएस मरीजों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने के नियमों का पालन नहीं करते, वे ऐसे मरीजों के लिए न तो ओपीडी में (अनिवार्य 25 प्रतिशत) और न ही 10 प्रतिशत बिस्तरों का ही आरिक्षत करते हैं।

कुछ अस्पतालों में अनुपालन की दर महज 3.3 प्रतिशत जितनी कम है।

शिक्षा

कांग्रेस सरकार का दावा है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है!!

वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार ने 80 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि आबादी हर साल 4–5 लाख बढ़ रही है।

दिल्ली में साक्षरता दर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों तथा केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा जैसे राज्यों से भी कम है।

दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों के कम से कम 12000 पद रिक्त पड़े है। बहुत से शिक्षक क्लैरिकल और गैर–शिक्षण कार्य करने के लिए विवश हैं।

दिल्ली के ज्यादातर सरकारी स्कूलों खेल के मैदान नहीं हैं।

स्कूलों में बुनियादी ढांचा चरमरा गया है।

आरटीई के नियमों के मुताबिक 1:30 का शिक्षक–छात्र अनुपात होना चाहिए। इसके विपरीत सरकारी स्कूलों में हर एक कक्षा में 80–100 बच्चे हैं।

बीजेपी के एक सर्वेक्षण तथा प्रमुख गैर–सरकारी संगठन ''प्रथम'' की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहद खराब है।

शिक्षकों के लिए कामकाज की स्थितियां बहुत निराशाजनक है, छठें वेतन आयोग के उचित कार्यान्वयन का अभाव है, 30 प्रतिशत शिक्षक साल भर क्लैरिकल ड्यूटीज और अन्य गैर–शिक्षण कार्य करते हैं।

लाडली योजना

कांग्रेस सरकार का दावा है कि लाडली योजना से 5.8 लाख लड़कियां लाभान्वित हुई हैं।
लेकिन सीएजी ने इस दावे की कलई खोल दी है। सीएजी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार करीब 42 प्रतिशत नामांकित लड़कियां योजना से हट चुकी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2010–12 में 125,808 मामलों का नवीकरण लंबित था, लेकिन महज 73,108 मामलों (यह महज 58.11 प्रतिशत है) का ही नवीकरण किया जा सका।

सीएजी का निष्कर्श है कि इस योजना को लक्षित लाभार्थियों का जरूरी डाटा प्राप्त किये बगैर ही शुरू कर दिया गया।

<u>आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए शिक्षा</u>

कांग्रेस सरकार का दावा है कि ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले छात्र निजी स्कूलों के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल्ली सरकार के बढ–चढ़ कर किये गये दावों को एडजेस्ट करने के बाद भी हर साल 15000 सीटें खाली रहती हैं और इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

उच्च शिक्षा

दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 15 वर्शों में दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई नया कॉलेज नहीं जोड़ा गया।

दिल्ली के ज्यादातर छात्र, कॉलेजों की कमी के कारण डीयू के कॉलेजों में दाखिला पाने में नाकाम रहते हैं। कांग्रेस सरकार का दावा है कि दिल्ली में उच्च शिक्षा सुविधाएं और वातावरण में सुधार हुआ है।

लेकिन, हकीकत यह है कि दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है।

अनधिकृत कालोनियां

कांग्रेस सरकार का यह कहना है कि उसने अनधिकृत कालोनियों में सर्वांगीण विकास किया है।

सच्चाई इससे बिलकुल भिन्न है।

पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने सैकड़ों अनधिकृत कालोनियों के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों को प्रॉविजनल रेगुलराइजेसन सर्टिफिकेट बंटवाये थे। ये प्रमाणपत्र कांग्रेस की राश्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा बांटे गये थे।

अब उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सीएजी ने अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है।

सीएजी ने प्रॉविजनल सर्टिफिकेट दिये जाने में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बताई है।

सीएजी ने कालोनियों के क्षेत्र की पहचान करने में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई है। कुछ कालोनियों को नियमित करने के लिए उनकी जनसंख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, जबकि अन्य मामलों में खाली प्लाटों को भी कालोनियों के नक्शे में शामिल किया गया।

इन सभी प्रक्रियाओं में कांग्रेस सरकार ने 28,00 करोड़ रूपये का घोटाला किया किन्तु इससे इन अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं हुआ।

झुग्गी–झोपड़ी कलस्टर

कांग्रेस सरकार ने गरीब लोगों के लिए 14,844 फ्लैटों के निर्माण का दावा किया है लेकिन उसने झुग्गी–झोपड़ी वालों को यह नहीं बताया कि उसने 60,000 फ्लैटों का वायदा किया था।

लाभार्थियों को अभी तक कोई भी फ्लैट नहीं दिये गये हैं।

दिल्ली मानव विकास रिपोर्ट (डीएचडीआर) 2013 में कहा गया है कि झुग्गी–झोपड़ी कलस्टरों में रहने वाले लोगों में से आधे से अधिक के पास अपने घर में शौचालय की सुविधा नहीं है और उन्हें बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। इसके कारण महिलाओं और बच्चों को अपराध और बीमारी का खतरा रहता है।

वर्ष 1993 और 1998 के बीच भाजपा शासन के दौरान प्रत्येक झुग्गी–झोपड़ी कलस्टर में बस्ती विकास केन्द्र था, जहां उनके लिए कौशल विकास के प्रशिक्षण और शिक्षा की व्यवस्था थी जिससे कि उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। इन केन्द्रों का उपयोग समुदाय केन्द्र के रूप में भी किया जाता था जहां विवाह और अन्य सामुदायिक कार्यक्रम तथा त्यौहार आदि मनाये जाते थे।

यूडीएचआर के परशेप्सन सर्वे के अनुसार झुग्गी–झोपड़ी कलस्टरों और इसी प्रकार की अन्य बस्तियों में बिजली की अनियमित सप्लाई, भारी भरकम बिजली के बिल आना सामान्य समस्या है।

परिवहन

कांग्रेस सरकार का यह दावा है कि उसने परिवहन व्यवस्था में सुधार किया है।

किन्तु सच्चाई यह है कि डीटीसी की बेड़े की आधी बसें ब्रेक डाउन और घटिया रख रखाव के कारण डिपो में खड़ी हैं। इससे डीटीसी को भारी नुकसान हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 2011–12 में 2,335.13 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।

कांग्रेस सरकार मोनो रेल की बात करती है, किन्तु उसने स्वयं स्वीकार किया है कि यह काम 2017 से पहले शुरू नहीं हो सकता। सरकार ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है और सब कुछ कागजों पर ही है।

कांग्रेस सरकार दिल्ली में सीएनजी परिवहन शुरू करने का श्रेय लेती है, जबकि सच्चाई यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक वाहनों में सीएनजी के प्रयोग का आदेश दिया था।

कांग्रेस सरकार ने परिवहन विभाग में कुप्रबंधन ही नहीं किया, बल्कि परिवहन घोटाला भी किया जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री लिप्त थे।

लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों का रख रखाव उचित रूप से नहीं किया जा रहा है और सीएजी ने इसके लिए लोक निर्माण विभाग की कड़ी आलोचना की है।

कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने डीटीसी की बेड़े में 1700 बसों का इजाफा किया है किन्तु अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

डीएचडीआर 2013 के परशेप्सन सर्वे के अनुसार दिल्ली के दो तिहाई लोगों ने बताया कि उनके इलाकों में सड़कों की स्थिति बदतर है।

झुग्गी–झोपड़ी कलस्टरों और अनधिकृत कालोनियों में सड़कों की हालत सबसे ज्यादा खराब है जहां कालोनियों के अंदर वाली सड़कों की उचित मरम्मत नहीं होती और स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जलतीं।

खाद्य सुरक्षा

कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने 15 वर्शों के शासन के दौरान खाद्य सुरक्षा दी है। किन्तु सच्चाई और दिल्ली में खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने हुई हड़बड़ी एक अलग ही कहानी कहती है।

सरकार के अनुसार खाद्य सुरक्षा अध्यादेश से दिल्ली की कुल आबादी अर्थात 1.67 करोड़ लोगों में से 73.5 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी। इसका यह अर्थ है कि अब तक दिल्ली की आधी आबादी को कांग्रेस के 15 वर्शों के दौरान कोई खाद्य सुरक्षा नहीं मिली।

आर.टी.आई. के माध्यम से भी कांग्रेस के दोहरे मापदंड का पता चला है।

मई, 2013 में एक आर.टी.आई. आवेदन द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार अन्नश्री योजना के अधीन केवल 7,220 लोगों को ही लाभ मिला था, जबकि इस योजना के अधीन 5,74,428 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया था।

दिल्ली की दो करोड़ की जनसंख्या के लिए केवल 2,500 राशन की दुकाने हैं।

पर्यावरण

कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने दिल्ली में पर्यावरण में सुधार किया है।

किन्तु दिल्ली अभी भी देश का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है।

डीएचडीआर के अनुसार दिल्ली में वन क्षेत्र घटा है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा करवाये गये अध्ययन में यह पाया गया है कि दिल्ली "हाई हेल्थ रिस्क" जोन में आता है। जिसका यह अर्थ है कि आउट डोर पार्टीकुलेट मैटर में खतरनाक रूप से वृद्धि हुई है।

दिल्ली की आबादी पिछले 10 वर्षों में 21 प्रतिशत बढ़ी है और यह जारी है।

कांग्रेस सरकार ने 3,000 करोड़ रूपये का यमुना नदी सफाई घोटाला किया है।

पिछले 15 वर्शों में हजारों करोड़ रूपये खर्च करने के बावजूद कांग्रेस सरकार यमुना को साफ करने में असफल रही है।

प्रशासन बनाम भ्रष्टाचार

कांग्रेस सरकार दिल्ली में बेहतर प्रशासन देने की बात करती है जबकि अनेकों घोटाले कुछ और ही बताते हैं।

कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के कई अन्य मामलों और घोटालों में लिप्त रही है।

वर्ष 2012 में सीबीआई ने दिल्ली सरकार द्वारा एन्टी बॉयोटिक शॉट के क्रय में 10 करोड़ रूपये का घोटाला पाया था, जो बैंगलोर की एक बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनी से ऊंची दरों पर खरीदी गई थी।

वर्श 2011 में सीएजी ने राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी में मुख्यमंत्री कार्यालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस पर 28,054 करोड़ रूपये खर्च हुये जो 296 करोड़ रूपये के मूल अनुमान से 100 गुना अधिक है।

उसी वर्ष दिल्ली के लोकायुक्त ने एक बैंक्वेट हाल के मालिक के विरूद्ध कर अपवंचन की जांच में बाधा डालने का प्रयास करने के लिए कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को हटाने की सिफारिश की थी।

कांग्रेस सरकार ने 1,600 अनधिकृत कालोनियों के नियमितिकरण के नाम पर 2,800 करोड़ रूपये का घोटाला किया।

समाज कल्याण

कांग्रेस सरकार का दावा है कि उसने 14 लाख बुजुर्गों को लाभ पहुंचाया है, जबकि वह केवल 4 लाख बुजुर्गों को ही पेंशन देती है।

कांग्रेस सरकार का दावा है कि वह जन आहार केन्द्रों से 15 रूपये में "हेल्दी फूड" देती है। सच्चाई यह है कि यह खाना हेल्दी नहीं है और चूंकि यह योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई थी इसकी गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आई है। हजारों लोगों ने विशेश रूप से दिहाड़ी मजदूरों ने शिकायत की है कि प्रति प्लेट भोजन की मात्रा भी कम हो गई है।

लगभग 50,000 गृहविहीन लोग अभी भी दिल्ली की सड़कों पर रहते हैं।

डीएचडीआर 2013 के परशेप्सन सर्वे में कहा गया है कि अनधिकृत कालोनियों में 70 प्रतिशत और झुग्गी झोपड़ी कलस्टरों की आधी आबादी ने बताया कि जल उपलब्धता की मात्रा उनके क्षेत्र में औसत से कम है।

कैसा ये विकास का शहर ?

मूलभूत सुविधाओं को तरसता शहर !

बदतर स्वास्थ्य सेवाओं का शहर !

महंगे बिजली, पानी के बिलों का शहर !

क्यों झुग्गी मे रहने को मजबूर शहर !

टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम का शहर !

बेदम सरकारी स्कूलों का शहर !

महिलाओ से बलात्कार का शहर !

कांग्रेस के 15 साल, दिल्ली हुई क्यों बेहाल

14 Pandit Pant Marg, New Delhi - 110001

011-23712323 or 011-23712744

www.bjpdelhi.org, info@bjpdelhi.org

/BJPDelhi /BJPDelhiState /BJPDelhiState

भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश